



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224060
CG-DL-E-31122020-224060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जौंच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

मामला संख्या: (एसएसआर) 22/2020

विषय: यूरोपीय संघ और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फेनोल" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/41/2020-डीजीटीआर.—

- यतः मै. दीपक फेनोलिक्स लि. तथा मै. हिंदुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल लि. (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फेनोल" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और निर्णायक समीक्षा करने तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं.14/13/2014-डीजीएडी के माध्यम से यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित मूल जाँच की शुरुआत की गई थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं.14/13/2014-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.6/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में निम्नानुसार परिभाषित "फेनोल" है :
"फेनोल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सामान्यतः वर्गीकृत एक मूल कार्बनिक रसायन है। इस उत्पाद को दो रूपों – बल्क और पैकड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियां सामान्यतः खुले रूप में होती हैं जबकि पैकड खेपें काफी छोटे कंटेनर भार में हो सकती हैं और उन्हें सामान्यतः ड्रम में पैक किया जाता है। फेनोल का प्रयोग फेनोल फार्मैल्डीहाइड रेजिन, लेमिनेट, प्लाइवुड, पार्टीकल बोर्ड, विसफेनोल-ए, एल्काइल फेनोल, भेषजों, डीफिनाइल ऑक्साइड आदि में किया जाता है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 29071110 के अधीन वर्गीकृत है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।"
5. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले हुई जाँच में यथापरिभाषित के समान है। फेनोल को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप शीर्ष 2907.11 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यात संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत हेतु आवेदन मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड और दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने जाँच अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित हैं।
8. उक्त के मद्देनजर और आवश्यक जाँच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने यूरोपीय संघ और सिंगापुर में प्रचलित कीमतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस प्रयोजनार्थ आवेदकों ने यूरोपीय संघ में कीमतों के निर्धारण हेतु यूरोस्टेट डेटा तथा सिंगापुर में कीमतों के निर्धारण हेतु आईसीआईएस मासिक कीमतों के अनुसार भारित औसत सौदा कीमतों पर भरोसा किया है।
10. कीमतों को कारखाना द्वार स्तर पर लाने के लिए उनमें संगत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो जाँच की शुरुआत को सही ठहराते हैं।

निर्यात कीमत

11. आवेदकों ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों हेतु निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए यूरोपीय संघ और सिंगापुर में समुद्री भाड़ा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा और व्यय, पत्तन व्यय और समुद्री बीमा के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं। इससे पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन कीमतों पर निर्यात हो रहा है। इस प्रकार निरंतर पाटन हो रहा है जो जाँच की शुरुआत को सही ठहराता है।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा कारणात्मक संबंध

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के कारण कीमत प्रभाव के चलते घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जिसकी वजह से जाँच अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में कमी हुई है, के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट के अनुसार विकृति आई है। आवेदक ने सूचित किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो निरंतर पाटन आयातों, भारी पाटन मार्जिन, मौजूदा अप्रयुक्त क्षमताओं, तीसरे देशों में पाटन मार्जिन और चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू करने को पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करने के कारक के रूप में प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना को दर्शाती है।

निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत

14. और अतः आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतत् द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

संबद्ध देश

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए संबद्ध देश यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर हैं।

जाँच की अवधि

16. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 (12 महीने) की है और क्षति जाँच अवधि में 2016-17, 2017-18, और अप्रैल, 2018- जून, 2019 तथा पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 14/13/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in तथा dir14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एम एस वर्ल्ड फॉर्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एम एस एक्सल फॉर्मेट में हों।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जाँच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय-सीमा

24. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ईमेल पत्तों पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना तथा अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जब उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जाँच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी.बी.स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

Case No. (SSR) 22/2020

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on Imports of Phenol originating in or exported from European Union and Singapore

F. No.7/41/2020-DGTR.—

1. Whereas M/s Deepak Phenolics Ltd. and M/s Hindustan Organics Chemical Ltd (hereinafter referred to as the “Applicants”), have filed an Application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the Domestic Industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Rules”), for sunset review of Anti-Dumping duty imposed on imports of Phenol (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from European Union and Singapore (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Background

3. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union, Korea RP and Singapore vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated 15th October, 2014. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated 12th January, 2016 recommending imposition of definitive Anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from European Union, Korea RP and Singapore. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 6/2016 – Customs (ADD) dated 8th March, 2016.

Production Under Consideration

4. The Product Under Consideration is “Phenol” was defined in the original investigation as follows:
“Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl oxide etc. The product is classified under Customs Tariff heading no. 29071110. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”
5. Since the present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Phenol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2907.11. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

6. The Applicants have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the Applicants and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. Therefore, subject goods produced by the Applicants are being treated as ‘like article’ to that being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

Domestic Industry and Standing

7. The Application for initiation of sunset review has been filed by M/s Hindustan Organics Chemicals Ltd. and Deepak Phenolics Ltd. As per available information, the production of the Applicants accounts for a major proportion in the domestic production of the subject goods in the country. The Applicants have claimed that

neither they have imported the PUC from the subject countries in the period of investigation nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.

8. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

Normal Value

9. The Applicants have claimed normal value by considering the prices prevailing in European Union and Singapore. For this purpose, the Applicants have relied upon weighted average of transaction prices as per Eurostat data for determination of prices in European Union, and ICIS monthly prices for determination of prices in Singapore.
10. Relevant adjustments have been made to the prices to bring them at ex-factory level. There is sufficient evidence of normal value claimed for the subject goods in subject countries to justify initiation of investigations.

Export Price

11. The Applicants have claimed export prices for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, commission, inland freight expenses, port expenses and marine insurance in European Union and Singapore to arrive at ex-factory export price.

Dumping Margin

12. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above de minimis level, but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being exported at dumped prices, thus, indicating continued dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury And Casual Link

13. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of price effect due to price under cutting and price depression leading to reduced profits, cash profits and Return on Capital Employed during the Period of Investigation as compared to preceding year. It is also noted that the Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of decline in capacity utilization, profits, cash profits and return on investments as compared to preceding year. The Applicant has provided information with regard to continued dumped imports, significant dumping margin, existing unutilized capacities, dumping margin in third countries and imposition of Anti-dumping duty by China as factors establishing likelihood of continuation or recurrence of dumping and recurrence of injury to the domestic industry should anti-dumping duty is allowed to lapse. The information provided by the applicant, prima facie, shows continuation of dumping of subject goods from subject countries, and likelihood of injury to domestic industry in case of cessation of the Anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

14. And therefore, on the basis of the duly substantiated application of the Applicants, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Countries

15. The subject countries in the present sunset review investigation are European Union and Singapore.

Period of Investigation

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st July, 2019 to 30th June, 2020 (12 Months) and the injury investigation period is from 2016-17, 2017-18 and April, 2018-June 2019, and POI.

Procedure

17. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated

12th January, 2016.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known producer/ exporters in the subject countries, their Government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the Domestic Industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority